RNI Number:
HPHIN/2019/78801

हिमाचल ग्रामीण

हिन्दी साप्ताहिक

डाक पंजीकरण संख्या: L/SLN3000043621/2021-23

जन-जन की आवाज़

❐वर्ष 02 ❐अंक 44 ❐सोलन, बुधवार 25 अगस्त से 31 अगस्त 2021 ❐मूल्य एक रुपए

► E-mail address: himachalgrameen@gmail.com ►

► पृष्ठ चार पर ► अनुराग सिंह ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत

सीएम के निर्देश : जिला स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष बल दें उपायुक्त

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड–19 मामलों में अचानक आई वृद्धि को देखते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिये। वह आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ कोविड–19 स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस के लगभग 2700 सक्रिय मामले हैं और यह चिंता का विषय है कि बहुत ही कम समय में मामलों में वृद्धि हुई हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश मामले सामने आए हैं, जबकि प्रमुख पर्यटन स्थलों सहित शहरी क्षेत्रों में बहुत कम मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि पर्यटकों के आगमन का राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कह कि इस महामारी के फैलने के प्रमुख कारण सामाजिक समारोह, विवाह समारोह, दावतें आदि हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजनयुक्त और सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन कन्संट्रेटर, परीक्षण किट और वेंटिलेटर हैं और 28 अतिरिक्त पीएसए संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि आठ पीएसए संयंत्रों पर कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा 31 अगस्त, 2021 तक दस और पीएसए संयंत्रों के कार्य पूर्ण हो जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और किन्नौर के जिला प्रशासन को इन जिलों के विभिन्न हिस्सों में चल रहे सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए और प्रतिबंध लगाने और स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य ने टीकाकरण अभियान में शून्य प्रतिशत बर्बादी के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान को तीव्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि टीकाकरण इस वायरस को रोकने का सबसे सुदृढ़ उपाय है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल–स्पीति जिलों ने पहली खुराक के लक्ष्य को शत–प्रतिशत पूरा कर लिया है और दस दिनों के भीतर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 29 प्रतिशत लोगों ने दूसरी खुराक ली है और नवम्बर, 2021 तक राज्य के सभी लोगों का टीकाकरण कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को पीएसए संयंत्रों की स्थापना के लिए सिविल और विद्युत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को यह सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि सीमा और अन्य क्षेत्रों में चेकिंग की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग की निधि और मानव संसाधन को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जिलों को सेब सीजन के दौरान सड़कों के रख–रखाव और वाहनों के सुचारू संचालन की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने जिला के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंचायतों और उप–मंडल स्तर की टीमों को और अधिक सक्रिय किया जाए। उन्होंने सूक्ष्म योजनाओं की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इन पंचायतों में कोविड–19 मामलों की निगरानी के लिए 10–12 पंचायतों के लिए एक कोविड अधिकारी तैनात किया जाए।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में 4–5 दिनों के भीतर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी जाएगी। अब केवल 124 कोरोना संक्रमित लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।

उपायुक्तों ने मुख्यमंत्री को अपने जिलों में सक्रिय मामलों, बिस्तरों की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं से अवगत कराया।

प्रधान सचिव राजस्व के.के. पंत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विकास को जनसुलभ बनाने में बीडीओ महत्वपूर्ण–कृतिका कुल्हरी

ग्रामीण स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

✍निशा कुमारी

सोलन। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने तथा विकास को जन सुलभ बनाने में विकास खण्ड अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सोलन जिला के पांचों विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं की समुचित जानकारी देना व पात्रता अनुसार उन्हें लाभान्वित करने में खण्ड विकास अधिकारियों को अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी खण्ड विकास अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण करें। उपायुक्त ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा की दिहाड़ी समय पर प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपने–अपने विकास खण्ड में मनरेगा के तहत 90 दिन पूर्ण कर चुके श्रमिकों की सूची ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रेषित की जाए ताकि इन श्रमिकों को सरकार के निर्देशानुसार अन्य प्रदत्त लाभ प्रदान किए जा सके।

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों की दिहाड़ी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत लम्बित कार्यों को शीघ्र निपटाने के लिए खण्ड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यों की वर्तमान स्थिति का जायज़ा लें।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन सुनियोजित तरीके से किया जाए ताकि आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर के पास गंदे पानी की निकासी के लिए एक सोक पिट बनाया जाना चाहिए जल प्रदूषण से बचाव हो सके। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को इस दिशा में योजनाबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त उपायुक्त ज़फ़र इकबाल ने कहा कि सभी खण्ड विकास अधिकारियों को शत–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किए गए कार्यों की रिपोर्टिंग सही समय पर की जानी चाहिए ताकि इन्हें केन्द्र सरकार को समय पर प्रेषित किया जा सके। बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन जिला में मनरेगा के तहत वर्ष 2021–22 में 411094 कार्यदिवस अर्जित किए गए। इनमें धर्मपुर विकास खण्ड में 70371, कण्डाघाट विकास खण्ड में 44158, कुनिहार विकास खण्ड में 78290, नालागढ़ विकास खण्ड में 122659 तथा सोलन विकास खण्ड में 95616 कार्यदिवस अर्जित किए गए।

बैठक में विभिन्न विकास खण्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना, पंचवटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दीन दयाल अन्तोदय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। जिला कांगड़ा के चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का 16वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की जबकि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में युवा विज्ञानियों और डिग्रीधारकों से अपील की कि वे रोजगार की तलाश के बजाय रोजगार प्रदात्ता बनें। इसके लिए उन्हें स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। उनके ज्ञान का लाभ समाज, विशेषकर कृषि समुदाय को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक योगदान के अलावा, वे राज्य के कृषि क्षेत्र में भी योगदान दें। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के डिजी–लॉकर और वेबसाइट के अपडेटड वर्जन का भी लोकार्पण किया।

श्री आर्लेकर ने कहा कि अनुसंधान और तकनीक के माध्यम से नवाचार बड़े पैमाने पर कृषि समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय देश के हिमालयी राज्यों के कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विश्वविद्यालयों में एक है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी कृषि क्षेत्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस महामारी का वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है लेकिन कृषक समुदाय ने यह सुनिश्चित किया कि देश की घटती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सशक्त नेतृत्व मिल रहा है और उन्होंने इस संकट की घड़ी से देश को सफलतापूर्वक बाहर निकाला है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के डिजी–लॉकर और वेबसाइट के अपडेटड वर्जन का भी लोकार्पण किया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के जैनेटिक्स एण्ड प्लांट ब्रिडिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजन कटोच द्वारा लिखित पुस्तक राइसबीनः एक्सप्लॉयटिंग द न्यूट्रिशनल पोटेंशियल ऑफ एन अण्डरयूटिलाइजड लैग्यूम, आर.एस. चन्देल द्वारा लिखित पुस्तक पेस्ट्स ऑफ फ्रूट एण्ड प्लांटेशन क्रॉप्स, डॉ. आर.के. राजू द्वारा लिखित मेज–गोल्डन ग्रेन ऑफ हिमाचल प्रदेश और विश्वविद्यालय की संयुक्त रिपोर्ट का भी इस अवसर पर विमोचन किया गया।

इससे पूर्व, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में 1.13 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हरित अतिथि गृह का लोकार्पण किया।

पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार ने इस अवसर पर कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि 43 वर्ष पूर्व उनके मुख्यमंत्रीत्व काल के दौरान इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इन वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने देश के कृषि विश्वविद्यालयों के मध्य अपना एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों के विज्ञानियों के परिश्रम और अनुसंधान का ही परिणाम है कि आज भारत अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, जिसके परिणामस्वरूप कोरोना महामारी के दौरान देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन प्रदान करवाया गया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मेडल विजेताओं और डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि यह उनकी मेहनत और समर्पण का फल है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र द्वारा सुदृढ़ आधार प्रदान करने के फलस्वरूप कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश की आर्थिकी स्थिर रही है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हरिन्दर कुमार चौधरी ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह में 393 विद्यार्थियों को डिग्रियां आबंटित की गईं हैं जिनमें से 262 स्नातक, 110 स्नातकोत्तर और 21 पीएचडी धारक हैं। विश्वविद्यालय के आठ विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए जबकि दो पूर्व विद्यार्थियों नन्द लाल शर्मा और तिलक राज शर्मा को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इस स्वर्ण जयंती वर्ष से विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हिमाचल के 51 स्थानीय उत्पादों के पंजीकरण का कार्य आरम्भ करेगा।

अर्की उप चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए समिति गठित

सोलन, हिमाचल ग्रामीण। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हरी ने 50–अर्की निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों का सहयोग सुनिश्चित बनाने के लिए गठित जिला स्तरीय स्थाई समिति का विस्तार किया है।

यह समिति जिला दण्डाधिकारी सोलन की अध्यक्षता में गठित की गई है। सहायक आयुक्त सोलन को समित का नोडल अधिकारी एवं संयोजक नियुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी, क्षेत्रीय वन अधिकारी (मुख्यालय), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोलन के परियोजना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सोलन तृतीय वृत के अधीक्षण अभियन्ता, जल शक्ति विभाग सोलन के अधीक्षण अभियन्ता, प्रदेश विद्युत बोर्ड सोलन वृत के अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी सोलन तथा जिला सोलन के सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकत दलों के प्रतिनिधि समिति के सदस्य हैं।

उपमण्डलाधिकारी सोलन, उपमण्डलाधिकारी नालागढ़, उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट, उपमण्डलाधिकारी कसौली, तहसीलदार सोलन, तहसीलदार नालागढ़, तहसीलदार कण्डाघाट, तहसीलदार कसौली तथा तहसीलदार बद्दी को समिति का नया सदस्य ामित किया गया है।

50–अर्की निर्वाचन क्षेत्र के उप निवार्चन में आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन की सभी शिकायतों का निपटारा इस समिति द्वारा किया जाएगा।

सम्पादकीय

घर खरीददारों को समयबद्ध राहत प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश रेरा की भूमिका सराहनीय

रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) अपनी स्थापना के डेढ़ वर्षों के भीतर निष्पादन याचिकाओं का निपटान करने में देश के सभी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों में दूसरे स्थान पर है। पिछले डेढ़ वर्षों से कोविड महामारी के संकट काल के वाबजूद प्राधिकरण पूर्णतः कार्यशील है। प्राधिकरण द्वारा मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्राधिकरण ने ऑनलाइन सुनवाई करके बड़ी संख्या में मामलों के निर्णय लिए हैं। इससे पक्षकारों को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से प्राधिकरण कार्यालय में नहीं आना पड़ता है। शिकायतों की सुनवाई वेबैक्स के माध्यम से की जा रही है। आज तक वेबैक्स के माध्यम से 260 से अधिक सुनवाई की जा चुकी हैं, जिससे हितधारकों के लिए कोविड महामारी के दौरान अपने घर या कार्यालय से मामलों को आगे बढ़ाना आसान हो गया है। इन मामलों में आवास आवंटियों को 6 करोड़ 55 लाख रुपये वापिस करने के आदेश दिए गए हैं। इस राशि में से लगभग 76 लाख रुपये की राशि प्रमोटरों एवं बिल्डरों से पहले ही वसूल कर आवंटियों के बैंक खातों में जमा कर दी गई है।

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री के मामलों में घर के खरीददार के हितों के संरक्षण के लिए कुशल एवं पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाता है। बहुत ही कम समयावधि के दौरान 38 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं और 52 एजेंटों को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया है। इसके साथ–साथ प्राधिकरण ने पक्षों के बीच शिकायतों के मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए महत्वाकांक्षी पहल की है। इसके परिणामस्वरूप आवंटियों को 52 लाख रुपये वापिस कर दिए गए हैं। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लघंन के लिए बिल्डरों एवं प्रमोटरों पर रिफंड के अलावा 2 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया। अभी तक आवंटियों द्वारा 14 निष्पादन याचिकाएं दायर की गई हैं और 9 निष्पादन याचिकाएं स्वतः संज्ञान से दर्ज की गई हैं। बिल्डरों और प्रमोटरों से कुल 35 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया।

प्राधिकरण ने विनियमन संख्या 2,4 और 5 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करने के लिए तैयार की हैं। ये त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के वेब पोर्टल (सार्वजनिक डोमेन) पर उपलब्ध हैं, इससे विभिन्न हितधारकों के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। आवंटी, घर खरीददार इन त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से भूखण्डों (प्लाटों), घरों और अपार्टमेंट के निर्माण एवं विकास कार्य की प्रगति स्वतः आसानी से देख सकते हैं। वेबएक्स बैठकों के माध्यम से प्रवर्तकों को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की नई वेबसाइट एनआईसी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में है। इसमें हिमाचल प्रदेश में सभी एस्टेट परियोजनाओं और एजेंटों के ऑनलाइन पंजीकरण, शिकायत दर्ज करने, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और पूर्व पंजीकरण सुविधाओं के लिए चार मॉडयूल की सुविधा होगी। यह सभी हितधारकों यानी प्रमोटरों, एजेंटों और आवंटियों की मदद करने के लिए एक सरल पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित वेबसाइट होगी।

वैबसाइट में पूर्व पंजीकरण की सुविधा का प्रावधान भी किया जाएगा। यह सुविधा प्राप्त होने से प्रमोटरों व बिल्डरों को विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमोदन शीघ्र प्राप्त करने में मदद मिलेगी और हिमाचल प्रदेश रेरा इसकी नियमित रूप से निगरानी एवं समय–समय पर अद्यतन (अपडेट) करने के साथ–साथ सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर वांछित अनुमोदन शीघ्र प्रदान करवाने में सहयोग भी करेगा।

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण, बल्कि रियल एस्टेट को विनियमित कर पारदर्शी कार्य प्रणाली भी सुनिश्चित कर रहा है।

लीक से हटकर कार्य करें: अधिकारी : मुख्यमंत्री

▪ हिपा के ई–ऑफिस और वॉल–ई का भी शुभारम्भ किया।

▪ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के कल्पतरू भवन का लोकार्पण

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। अधिकारियों को नवाचार विचारों के साथ आगे आना चाहिए और लीक से हट कर सोचना चाहिए ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नवीन कार्यक्रम और परिणामोन्मुखी नीतियां बनाई जा सकें। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के कल्पतरू भवन का लोकार्पण करने के उपरान्त हिमाचल प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कही। इस भवन का निर्माण 4.34 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने हिपा के ई–ऑफिस और वॉल–ई का भी शुभारम्भ किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है और सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा की पहचान करना महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें ताकि वह आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जो भी कार्य प्रदान किया गया है उसे प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी धारणा बनाई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिकारी आम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अधिक उत्साह से कार्य करें। उन्होंने कहा कि नई सोच के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों से वे लोगों के जीवन पर अमिट छाप छोड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और योजनाओं का लाभ सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को मिले। अधिकारियों को लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए ताकि विकासात्मक परियोजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण युवा अधिकारियों के लिए है, जो सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए प्रशिक्षण मुख्य रूप से उनके बुनियादी ज्ञान, कौशल और व्यवहार में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से उनकी दक्षता और संवेदनशीलता पर केन्द्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक, पुलिस, राजस्व, विकास, कर–प्रशासन और अन्य सम्बन्धित विभागों में चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण के अन्तर्गत सरकारी विभागों के सामान्य कार्य के अतिरिक्त बुनियादी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

जय राम ठाकुर ने नागरिक/राजस्व प्रशासन के विभिन्न पहलूओं, विशिष्ट अधिनियमों पर व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए हिपा की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जनता की शिकायतों का घरों के निकट निवारण सुनिश्चित किया, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत न आने वाले लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमकेयर योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के परिवारों को 3000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने के लिए सहारा योजना शुरू की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ. राजीव बंसल और डॉ. मनोज शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक सिटीजन इम्पॉवरमेंट–ए स्टडी ऑफ ई–गवर्नेंस सर्विसिज और डॉ. राजीव बंसल द्वारा लिखित पुस्तक स्टैपिंग स्टोनज–ए कम्पेंडियम ऑफ केस स्टडीज का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एचएएस प्रशिक्षुओं से बातचीत भी की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की।

सचिव प्रशासनिक सुधार एवं ग्रामीण विकास और पंचायती राज संदीप भटनागर ने कहा कि प्रशिक्षुओं को सरकारी कार्य की बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिपा के पास योग्य और प्रशिक्षित इन–हाउस फैकल्टी है, जो सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले नए अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करने में रूचि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि व्यस्कों की शिक्षा और प्रशिक्षण के तरीके को समझते हुए, हिपा का हमेशा यह प्रयास रहता है कि प्रशिक्षण के उन सभी तरीकों का उपयोग किया जाए जो एक व्यस्क की सीखने–समझने की क्षमता के अनुसार हों।

हिपा के निदेशक विवेक भाटिया ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत करते हुए कहा कि नया परिसर राज्य सरकार के अधिकारियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 19 नवनियुक्त एचएएस (हिमाचल प्रशासनिक अधिकारियों) और अन्य सिविल सेवा अधिकारियों ने 8 सप्ताह के फाउंडेशन कोर्स में भाग लिया, जो एक जुलाई से शुरू हुआ और इस माह की 28 तारीख को समाप्त होगा। इन अधिकारियों में नौ हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी, एक हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा अधिकारी, दो तहसीलदार, तीन खंड विकास अधिकारी, दो जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी, एक जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और एक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए हिपा में खेल परिसर का निर्माण किया जाना चाहिए।

हिपा की अतिरिक्त निदेशक ज्योति राणा ने कार्यक्रम का संचालन किया और धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।

एचएएस प्रशिक्षुओं डॉ. विवेक गुलेरिया और शिखा पटियाल ने हिपा में आयोजित दो माह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। दोनों प्रशिक्षुओं ने हिपा के प्रबंधन द्वारा उठाए गए अभिनव कदमों की सराहना की।

इस अवसर पर भाजपा नेत्री विजय ज्योति सेन, हिपा के संकाय सदस्य सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि श्री कल्याण सिंह वरिष्ठ राजनेता, दूरदृष्टा और कुशल प्रशासक थे। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गरीब, पिछड़े और समाज के सबसे निचले वर्ग के लिये बहुत काम किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने की श्री कल्याण सिंह में अदभुत क्षमता थी और वह सच्चे धर्मानुयायी थे। जब वह राज्यस्थान के राज्यपाल थे तो कुछ समय के लिये उनके पास हिमाचल के राज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार रहा। समाज को दिये गए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

श्री आर्लेकर व जय राम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की है और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

महिला मोर्चा की सदस्यों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधी राखी

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को आज यहां उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने अध्यक्षा रश्मि धर सूद की अध्यक्षता में रक्षा बन्धन के अवसर पर राखी बांधी। इस अवसर पर वन्दना गुलेरिया और मोर्चा की अन्य सदस्य भी उपस्थित थीं।

ब्रह्मकुमारी व शिमला में रहने वाले तिब्बती समुदाय की प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को उनके सरकारी आवास पर राखी बांधी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा बन्धन एकता का पवित्र पर्व है, जो भाई और बहन के बीच प्रेम को और अधिक प्रगाढ़ करता है।

नगर परिषद परवाणू के मनोनीत पार्षदों को दिलाई शपथ

सोलन, हिमाचल ग्रामीण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल की गरिमामयी उपस्थिति में आज नगर परिषद परवाणू के मनोनीत पार्षदों को उपमण्डलाधिकारी कसौली डॉ. संजीव धीमान ने शपथ दिलाई।

इस अवसर पर मनोनीत पार्षद राम ध्यान सिंह, विनोद कुमार ठाकुर, विनीत गोयल तथा राम कुमार घई को शपथ दिलाई गई।

डॉ. सैजल ने इस अवसर पर मनोनीत पार्षदों को बधाई देते हुए आशा जताई कि सभी पार्षद अपने–अपने क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास एवं परवाणू शहर के सौंदर्यीकरण में समुचित सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने सभी पार्षदों से आग्रह किया कि परवाणू नगर के वासियों के समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हल करने में सहयोगी बनें।

आयुष मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

इस अवसर पर नगर परिषद परवाणू के पार्षदगण, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप, भाजपा मण्डल कसौली के अध्यक्ष कपूर सिंह वर्मा, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य राजकुमार सिंगला सहित अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

डॉ. राजीव सैजल द्वारा कसौली एसडीएम कार्यालय का विधिवत शुभारम्भ

सोलन, हिमाचल ग्रामीण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने आज सोलन जिला के कसौली में उपमण्डलाधिकारी कार्यालय का विधिवत शुभारम्भ किया।

दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय कसौली का विधिवत शुभारम्भ पुरातन लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह कसौली परिसर में किया गया।

डॉ. सैजल ने इस अवसर पर कसौली विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उपमण्डलाधिकारी कार्यालय कसौली के विधिवत शुभारम्भ से क्षेत्रवासियों की चिर लम्बित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के विधिवत शुभारम्भ से अब लोगों को अपने राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए सोलन नहीं जाना होगा।

आयुष मंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सेवा की भावना के साथ काम को त्वरित गति से निपटाने के लिए कार्यरत रहें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से जन–जन तक पहुंचती है और यदि सेवा की भावना के साथ कार्य किया जाए तो आमजन की अनेक समस्याओं का बिना किसी हस्तक्षेप के निदान किया जा सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि मूलभूत सुविधाओं से सम्बन्धित अपेक्षाओं और समस्याओं का त्वरित निदान किया जाना चाहिए।

डॉ. सैजल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं को उनके घरद्वार के समीप निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति में जनमंच विशेष रूप से सफल रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार और जनता के मध्य सीधा संवाद स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण की दिशा में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 आम आदमी का संबल बनकर उभरी है। इसके माध्यम से अब तक 2. 48 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश का निपटारा सुनिश्चित बनाया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र को आदर्श बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कसौली एवं साथ लगते क्षेत्रों में पानी की समस्या से निपटने और बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए 103 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास शीघ्र

करवाया जाएगा।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड–19 से बचाव के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित बनाएं और टीकाकरण अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 87 प्रतिशत से अधिक लोगों ने टीके की प्रथम खुराक ले ली है। लगभग 28 प्रतिशत लोग दूसरी खुराक भी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल इस दिशा में देश में प्रथम स्थान पर है।

डॉ. सैजल ने इस अवसर पर जनसमस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए।

भाजपा मण्डल कसौली के अध्यक्ष कपूर सिंह वर्मा ने उपमण्डलाधिकारी कार्यालय कसौली के शुभारम्भ के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गत साढ़े 03 वर्षों में कसौली विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है।

उपमण्डलाधिकारी कसौली डॉ. संजीव धीमान ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। तहसीलदार कसौली मनमोहन जिस्टू ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर, जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप, जिला सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष सुन्दरम ठाकुर, जिला परिषद सदस्य दर्पणा, बीडीसी धर्मपुर की अध्यक्ष जमना देवी, उपाध्यक्ष मदन मोहन मेहता, ग्राम पंचायत नाहरी के प्रधान हिमांशु गुप्ता, बीडीसी सदस्य चंपा ठाकुर एवं नरेश ठाकुर, भाजपा मण्डल सोलन के अध्यक्ष कपूर सिंह वर्मा, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य राज कुमार सिंगला, जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशक लाज किशोर शर्मा, ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल के उप प्रधान विपन, युवा बोर्ड के सदस्य मदन शांडिल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दौलत ठाकुर, भाजपा चिकित्स प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. मान सिंह ठाकुर, खेल प्रकोष्ठ के संयोजक रमेश अत्री, उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हरी, उपमण्डलाधिकारी कसौली डॉ. संजीव धीमान तहसीलदार मनमोहन जिस्टू सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, भाजपा

कैजुअल कलाकारों की स्क्रीनिंग के लिए 06 सितम्बर तक आवेदन आमन्त्रित

कलाकरों की स्क्रीनिंग 28 सितम्बर, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय सोलन में आयोजित की जाएगी।

सोलन, हिमाचल ग्रामीण। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय सोलन में नैमित्तिक (कैजुअल) आधार पर कलाकारों के लिए 06 सितम्बर, 2021 तक आवेदन आमन्त्रित किए गए हैं। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां दी।

उन्होंने कहा कि चयनित कलाकारों को कैजुअल आधार पर अनुबन्धित किया जाएगा। कलाकारों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम की दर पर भुगतान किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि इसके लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इच्छुक आवेदक दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा वह गायन, वादन, नृत्य व नाट्य कला में अनुभवी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवेदक सोलन जिला का ही निवासी होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उससे सुगमता से सम्पर्क किया जा सके।

प्रवक्ता ने कहा कि यह स्क्रीनिंग प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार के लिए फोक मीडिया कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूर्णतः कैजुअल आधार पर होगी। इसमें पुरूष तथा महिला कलाकार आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक कलाकार अपना आवेदन सादे कागज पर एक पासपोर्ट आकार फोटो सहित शैक्षणिक योग्यता व कला निष्पादन के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय सोलन में 06 सितम्बर 2021 तक भेज सकते हैं।

कलाकरों की स्क्रीनिंग 28 सितम्बर, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय सोलन में आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदक को किराया/भाड़ा व पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

अधिक जानकारी के लिए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय सोलन के दूरभाष नम्बर 01792–220089 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

खाद्य तेलों पर अनुदान से 18.71 लाख कार्डधारक लाभान्वित होंगे: मुख्यमंत्री

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं पर उचित अनुदान प्रदान कर राहत प्रदान की जा रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को 32 लाख लीटर खाद्य तेल प्रदान कर रही है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेलों में बी.पी. एल. परिवारों को 10 रुपये प्रति लीटर और ए.पी.एल. परिवारों को पांच रुपये प्रति लीटर रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उपभोक्ताओं को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने बी.पी. एल. परिवारों के लिए खाद्य तेलों पर आगामी चार महीनों के लिए अनुदान राशि दस रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति लीटर और ए.पी.एल. परिवारों के लिए पांच रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से अगले चार महीनों में उपभोक्ताओं को 13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 18. 71 लाख कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए समय–समय पर कई कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कुल्लू में किए 40 करोड़ रुपए लागत के लोकार्पण और शिलान्यास

जरी में उप-तहसील और भुंतर में नया विकास खण्ड खोलने की घोषणा की

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा कुल्लू जिला के विधानसभा क्षेत्र कुल्लू में लगभग 40 करोड़ रुपए लागत की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री खराब मौसम के कारण आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर नहीं जा पाये।

जय राम ठाकुर ने तहसील कुल्लू के खराहल गांव में एक करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना तलोगी, मटारना और तराकड़ा के सुधार कार्य, भुंतर तहसील में 1.01 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना (एलआईएस) पिरडी और ग्राम पंचायत चौंग में 1.05 रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना फाटी चौंग का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने 35.05 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इसमें ग्राम पंचायत चौपारसा में 1.71 करोड़ रुपए की लागत से लग वैली के शेष बचे गांव के लिए जलापूर्ति योजना, 5.67 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत मानगढ़ में जलापूर्ति योजना समालग, ग्राम पंचायत मशणा में जलापूर्ति योजना मशणा, ग्राम पंचायत चौपारसा में जलापूर्ति योजना ग्रामंग, ग्राम पंचायत बरामन में जलापूर्ति योजना डूगीलग–शिलधारी और ग्राम पंचायत फलाण में जलापूर्ति योजना फलाण, 9.62 करोड़ रुपए की लागत से ब्यास नदी से 16 टंकी शिलधारा उठाऊ जलापूर्ति योजना, तहसील कुल्लू में 2.95 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना (एलआईएस) न्यूली–थर्मान, तहसील कुल्लू में 1.91 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना न्यूली–थर्मान के सीएडी कार्य, उठाऊ सिंचाई योजना शमशी के लिए 2.11 करोड़ रुपए के सीएडी कार्य, तहसील कुल्लू की मोहल खड्ड पर 4.61 करोड़ रुपए की लागत से भण्डारण टैंक व रिचार्जिंग जलाशय, 97 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत कसोल में पीडबल्यडीएसएस छलाल, कटागला, रशोल और चोंज के अतिरिक्त नए स्रोत व सुधार, तहसील कुल्लू में 1. 58 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना टील–सांगचन और ब्राधा के संवर्धन, 3.07 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना शमसी के वितरण का नवीनीकरण कार्य और तहसील कुल्लू में 83 लाख रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना जिया के सीएडी कार्य शामिल हैं।

शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लगभग 2 वर्ष प्रभावित होने के बावजूद, राज्य सरकार ने पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान राज्य का समान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया है, उन्होंने कहा कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपने दौरों के दौरान लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य के पांगी और भरमौर क्षेत्रों के दौरे के दौरान उन्होंने लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के विकास के लिए प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि राज्य को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्नेह और मार्गदर्शन निरन्तर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान क्षेत्र की विकासात्मक मांगों को लेकर केन्द्र सरकार हमेशा संवदेनशील रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में राष्ट्र निरन्तर प्रगति और खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रदेश को हर सम्भव सहायता प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने जरी में उप तहसील और भुंतर में नया विकास खण्ड खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव तक रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए प्रथम चरण की वन स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए मामला भेजा गया है। इसके बनने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बिजली महादेव के लिए सड़क मार्ग को चौड़ा करने की भी घोषणा की बशर्ते इसके लिए भूमि उपलब्ध हो।

उन्होंने न्यूली माध्यमिक पाठशाला को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने, रामशिला के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नीचे एक पार्क विकसित करने के लिए पांच लाख रुपये देने, सियोगी सड़क के रख–रखाव के लिए तीन लाख रुपये और माता न्यूली रणी में सराय भवन निर्माण के लिए तीन लाख रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भुबू जोत सुरंग के निर्माण के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य केन्द्रीय नेताओं के साथ मामला उठाया है। इसके निर्माण से जोगिन्द्रनगर और कुल्लू के मध्य 60 किलोमीटर से अधिक दूरी कम होगी। जय राम ठाकुर ने करींगचा में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने, दोघरी स्कूल को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने समाणा से गुरूगग और जठाणी से मथसोर सड़कों को विकसित करने के लिए 25–25 लाख रुपये देने की भी घोषणा की, ताकि इन क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए विकसित किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने शीशामठी व शमशी बाई–पास के निर्माण के लिए 15 लाख रुपये और भलयाणी में सराय भवन के लिए 10 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में विकास की गति प्रभावित न हो। उन्होंने इस दौरान लगभग 42 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 4200 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री को अपना भरपूर सहयोग निरन्तर जारी रखें ताकि विकास की गति निर्बाध रूप से जारी रह सके।

कुल्लू के विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर ने कहा कि यह प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री मिले हैं, जो उनकी विकासात्मक मांगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं और साथ ही लोगों के सुझावों को भी महत्व देते हैं। उन्होंने क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

पूर्व सासंद महेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र के लिए सभी विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला स्वयं रखना चाहते थे, परन्तु खराब मौसम के कारण उन्हें वर्चुअल माध्यम से शिमला से यह परियोजनाएं जनता को समर्पित करनी पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिजली महादेव के लिए रोप–वे के निर्माण और रामशिला के निकट पार्क निर्मित करने का आग्रह किया।

विधायक बंजार सुरेन्द्र शौरी, जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सेन, राज्य भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर, एपीएमसी के सलाहकार रमेश शर्मा, भाजपा नेता युवराज बोध, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट में 4000 पदों को भरने की मंजूरी

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के चुराग में नया विकास खण्ड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जिला मण्डी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वींति भी प्रदान की गई।

शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला किया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच आधार पर शीघ्रता से भरे जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 250 मिलियन डॉलर (1813 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण किया जा सके। कुल 250 मिलियन डॉलर में से विश्व बैंक 160 मिलियन डॉलर (1160.32 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि 90 मिलियन डॉलर (652.68 करोड़ रुपये) का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया।

शिमला जल आपूर्ति और मल निकासी परियोजना के मुख्य उद्देश्य वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 एमएलडी के साथ शिमला जल आपूर्ति में संवर्द्धन, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुफरी, शोघी, घणाहट्टी और अतिरिक्त योजना क्षेत्र के लिए 2050 तक शिमला नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू और व्यवसायी उपभोक्ताओं के लिए सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र में बेहतर मलनिकासी सेवाएं प्रदान करना है।

इस परियोजना में शिमला जिले की सुन्नी तहसील के शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है जिसमें संजौली में 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाने और 22 कि.मी की पाइप बिछाने से 67 एमएलडी पानी की वृद्धि शामिल है। इस परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम शिमला में वितरण पाइप नेटवर्क को सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति प्रणाली में स्तरोनन्त करने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, शिमला के मैहली, पंथाघाटी, टूटू और मशोबरा क्षेत्रों में मलनिकासी प्रणाली प्रदान की जाएगी। यह राज्य के लिए एक प्रमुख परियोजना होगी जो शिमला में बेहतर जलापूर्ति और मलनिकासी प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करेगी और वर्ष 2050 तक शहर की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार का शहरी विकास विभाग कोविड–19 के कारण उत्पन्न वित्तीय बाधाओं के बावजूद विश्व बैंक और वित्त मंत्रालय से इस निधि को प्राप्त करेगा।

बैठक के दौरान राज्य में कोविड–19 की स्थिति और संभावित तीसरी कोरोना लहर से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों पर भी प्रस्तुति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने जिला बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सैद्धान्तिक रूप से नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्यूटी का लाभ देने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के चुराग में नया विकास खण्ड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जिला मण्डी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के एडीआर केन्द्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुलिपिकों के चार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जेबीटी के रिक्त पदों पर जेबीटी के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर–आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड बल्ह और सुन्दरनगर–1 को अलग कर सलवाहन में नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड कार्यालय सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। जिला चम्बा के राजकीय माध्यमिक पाठशाला दारवीं को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला लामू और बडग्रां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ इन स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के करसोग क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलधार को 30 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित करने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रक्कड़ को 24 घण्टे सेवाएं प्रदान करने वाले आपातकालीन चिकित्सा संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला के चमयाणा में निर्माणाधीन सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा कचरा प्रबन्धन स्थान और कैन्टीन तथा कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को एचएससीसी प्राइवेट इण्डिया लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में स्वर्ण जयंती समारोह तैयारियों की समीक्षा की

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने आज यहां प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण होने से सम्बन्धित आयोजनों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रशासनिक सचिवों ने शिमला से और जिला उपायुक्तों ने वर्चुअल माध्यम से अपने सम्बन्धित जिलों से बैठक में भाग लिया।

मुख्य सचिव ने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदेश की 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को दर्शाते हुए आयोजन आधारित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला उपायुक्तों से सम्बन्धित जिलों में प्रदेश के स्वर्ण जयंती समारोह पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए।

स्वर्ण जयंती समारोह के लिए की गई तैयारियों से मुख्य सचिव को अवगत करवाया। इन गतिविधियों में युवा उत्सव सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, टूरिज्म मार्ट और पौध रोपण गतिविधियां आदि शामिल हैं।

केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का शिमला में गर्मजोशी से स्वागत

शिमला, हिमाचल ग्रामीण। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के पहले दौरे के दौरान वीरवार सायं जिला शिमला भाजपा द्वारा होटल पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम में गर्मजोशी से स्वागत किया। केन्द्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में पांच दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा की शुरूआत की।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में अनुराग सिंह ठाकुर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पहाड़ी राज्य के लोगों की विकासात्मक मांगों, जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति सदैव तत्पर रहे हैं। इससे पूर्व, उन्होंने प्रदेश के सुपुत्र जगत प्रकाश नड्डा को विश्व के सबसे बड़े राजनैतिक दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में भारत को मजबूत राष्ट्र की पहचान प्राप्त हुई और राष्ट्र विश्व गुरू बनने की ओर अग्रसर है।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि उन्हें केन्द्रीय मंत्री के रूप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। वह राज्य के गौरव को बनाए रखने और लोगों की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने को समाज के सभी वर्गों के कल्याण और प्रदेश के तीव्र विकास विशेषकर उन लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा और हिमकेयर योजनाएं आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को बधाई दी, जो केन्द्र की योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके थे। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश कोविड–19 वैक्सीनेशन अभियान में अग्रणी है। उन्होंने राज्य के लोगों से हिमाचल को देश का मॉडल राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना आरम्भ करने और इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के साथ–साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने, जल जीवन मिशन इत्यादि केन्द्र सरकार की अनेक प्रमुख उपलब्धियां हैं।

इससे पूर्व, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और राज्य भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने स्वागत सम्बोधन किया।

इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी, विधायक बलवीर वर्मा, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, प्रदेश संगठन महामंत्री भाजपा पवन राणा, राज्य भाजपा उपाध्यक्ष और जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी संजीव कटवाल, राज्य भाजपा महामंत्री त्रिलोक जमवाल, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत मिला तीन करोड़ का ऋण : सुरेश भारद्वाज

व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कार्यान्वित की गई है योजना

शिमला, हिमाचल ग्रामीण।शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 3000 से अधिक लाभार्थियों को 3 करोड़ रुपये का गारंटी मुक्त ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब पार्षदों की मदद से स्ट्रीट वेंडर्स तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 3000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिल चुका है। उन्होंने कहा कि यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई है।

उन्होंने कहा की व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को आरम्भ किया है और प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा वर्तमान में प्रदेश में 5790 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिन्हें पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहेगा की सभी जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए समय–समय पर बैंक और सम्बंधित अधिकारियों से बात की जा रही है।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी पार्षद अपने–अपने वार्डों में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स से संपर्क कर, इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और यदि कोई इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी हर सम्भव सहायता करेंगे। उन्होंने शहरी विकास विभाग व शहरी निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकों से समय–समय पर इस योजना के बारे में संवाद स्थापित करें, जिससे कोई भी प्रार्थना–पत्र अधिक समय तक लंबित न रहे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपये तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल स्ट्रीट वेंडर्स अपनी पूंजी के तौर पर कर सकते हैं। इस योजना से भारत के 50 लाख वेंडर्स लाभान्वित होंगे, जो लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इस योजना के तहत एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। इस लोन के उपयोग से वेंडर्स को अपना व्यवसाय दोबारा आरम्भ करने में मदद मिलेगी। इस लोन पर आवेदक को किसी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी, वहीं लोन का पैसा समय पर जमा करने पर 7 फीसदी तक की ब्याज उपदान मिलता है। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने के इच्छुक स्ट्रीट वेंडर्स सीधे पीएम स्वनिधि योजना की वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर्स शहरी निकाय के कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक निशा कुमारी द्वारा क्वालिटी प्रिन्टर, निर्मला निवास, वार्ड–1, राजा का बाग, अर्की, जिला सोलन से मुद्रित व गांव व डाकघर बथालंग, तहसील अर्की, जिला सोलन से प्रकाशित।
मोबाईल: 70186-84867, ईमेल पता-himachalgrameen@gmail.com